

Chief Minister of a State

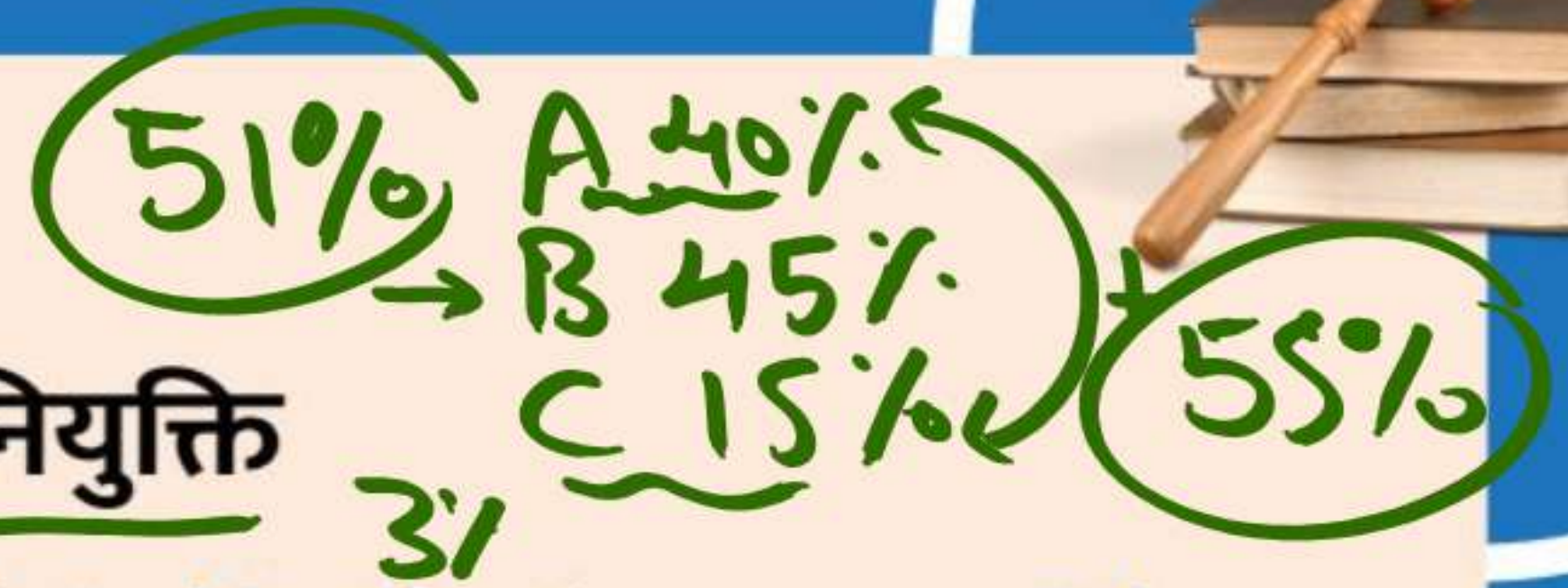


- The chief minister (CM) is the real executive head of the state government./
मुख्यमंत्री (CM) राज्य सरकार का असली कार्यकारी प्रमुख होता है।
- The Chief Minister is the de facto head of the state government, just like the Prime Minister at the Centre. मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक (de facto) प्रमुख होते हैं, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री।

Chief Minister of a State



• Appointment of Chief Minister / मुख्यमंत्री की नियुक्ति



1. Article 164 says that the chief minister shall be appointed by the Governor of the concerned state./ अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करेंगे।
2. Leader of the majority party in the Legislative Assembly is appointed as CM./ विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को CM नियुक्त किया जाता है।
3. If no clear majority – Governor may appoint leader of the largest party of coalition./ अगर साफ़ बहुमत नहीं है - तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को नियुक्त कर सकते हैं।
4. Must prove majority in the assembly within a stipulated time./ उन्हें तय समय के अंदर विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा।

Tenure and salary

Bjp

- **Term** : 5 years (co-terminus with the legislative Assembly)
- Holds office during the pleasure of the Governor.
- Salary and allowances decided by the state legislature.
- **कार्यकाल**: 5 साल (विधानसभा के साथ-साथ)
- राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं।
- सैलरी और भत्ते राज्य विधानमंडल तय करता है।

Qualifications

- Must be a citizen of India. ✓
- Must be a member of the state legislature (assembly or council)
- If not a member at the time of appointment – must get elected/nominated within 6 months
- भारत का नागरिक होना चाहिए। ✓
- राज्य विधानमंडल (विधानसभा या परिषद) का सदस्य होना चाहिए। ✓
- अगर नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है - तो 6 महीने के अंदर चुनाव/नामांकित होना चाहिए।

Mamata wins West Bengal but loses in Nandigram

TMC garners over 48% of votes; Left-Congress alliance rejected.

Updated - May 02, 2021 11:37 pm IST - Kolkata

SHIV SAHAY SINGH



READ LATER



The colour of victory: Trinamool activists celebrate in South Dinajpur district of West Bengal on Sunday.

Power and functions of the Chief Minister

Executive powers / कार्यकारी शक्तियाँ :

- ✓ Head of the council of ministers./ मंत्रिपरिषद का प्रमुख।
- ✓ Advises the governor on the appointment of other ministers./ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पर राज्यपाल को सलाह देता है।
- ✓ Allocated and reshuffles portfolios among ministers./ मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा और फेरबदल करता है।
- ✓ Coordinates the work of different ministries./ अलग-अलग मंत्रालयों के काम में तालमेल बिठाता है।
- ✓ Acts as a link between the Governor and council of ministers./ राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है।

Money bill

Legislative powers / विधायी शक्तियाँ

- ✓ Advises the Governor to summon or prorogue the Legislature./ विधानमंडल को बुलाने या स्थगित करने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है।
- ✓ Can recommend dissolution of Legislative Assembly to the Governor./ राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है।
- ✓ Announces Government policies on the floor of the House./ सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।



Financial powers / वित्तीय शक्तियाँ

- ✓ Plays key role in the preparation and presentation of the State budget./ राज्य बजट तैयार करने और पेश करने में मुख्य भूमिका निभाता है।
- ✓ Ensures that Money bills are introduced only with prior approval of the Government./ यह सुनिश्चित करता है कि मनी बिल केवल सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही पेश किए जाएं।

Advisory role to Governor / राज्यपाल को सलाह देने का रोल :

Under Article 167, the chief minister must/ आर्टिकल 167 के तहत, मुख्यमंत्री को ये करना होगा:

- ✓ Communicate to the Governor all decisions of the council of Ministers./ मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों के बारे में राज्यपाल को बताना होगा।
- ✓ Furnish information relating to the administration of the state./ राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी देनी होगी।
- ✓ Submit proposals for consideration by the council of Ministers if the Governor asks./ अगर राज्यपाल कहें तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्ताव सबमिट करने होंगे।

Role In the council of Ministers / मंत्रिपरिषद में रोल:

- ✓ CM is the head and leader of the council of ministers./ CM मंत्रिपरिषद का हेड और लीडर होता है।
- ✓ The council exists only as long as the CM enjoys the confidence of the Legislative / परिषद तभी तक रहती है जब तक CM को विधान सभा का भरोसा हासिल होता है। Assembly.
- ✓ If the CM resigns or dies – entire council of ministers automatically dissolves. / अगर CM इस्तीफा दे देता है या उसकी मौत हो जाती है - तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप खत्म हो जाती है।

Important article related to chief minister

Article No.	Subject-matter / विषय-वस्तु
Article 163 ✓	• Council of ministers to aid and advise the Governor. / राज्यपाल की सहायता और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद।
Article 164 ✓	• Other provisions as to Ministers, including appointment, tenure, and salaries. / मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन।
Article 166 ✓	• Conduct of Business of Government of a state. / राज्य सरकार के कार्यों का संचालन।
Article 167 ✓	• Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor etc. / राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य।
Article 177 ✓	• Rights of ministers as respects the houses. / सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार।

State council of Ministers



- The state council of ministers (CoM) is the real executive authority in the state./ राज्य में स्टेट काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स (CoM) ही असली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है।
- It aids and advises the governor, who acts as the constitutional head, similar to the relationship between the President and Union Council of Ministers at the centre./ यह गवर्नर की मदद और सलाह देती है, जो केंद्र में राष्ट्रपति और यूनियन काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स के बीच के रिश्ते की तरह ही संवैधानिक प्रमुख के तौर पर काम करता है।

State council of Ministers



Governor

Composition of COM / CoM का गठन:

- **Chief minister** – head of the council / काउंसिल का मुखिया
- **Cabinet minister** – in charge of important departments (e.g., Home, finance)/ महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी (जैसे, गृह, वित्त)
- **Ministers of state** – may have independent charge or assist cabinet Ministers/ इनके पास स्वतंत्र प्रभार हो सकता है या ये कैबिनेट मंत्रियों की मदद कर सकते हैं
- **Deputy Ministers** – assist ministers of state or cabinet Ministers / ये राज्य मंत्रियों या कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं

Appointment & tenure / नियुक्ति और कार्यकाल

- **The governor appoints the chief minister / राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।**
- **On the advice of the CM, the Governor appoints other ministers/ मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।**
- **Ministers hold office during the pleasure of the Governor/ मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं।**
- **The council is collectively responsible to the Legislative Assembly (Article 164(2))./ परिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 164(2))।**
- **Ministers take oath of office and secrecy before the Government./ मंत्री सरकार के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं।**



Responsibilities of the council/ परिषद की ज़िम्मेदारियाँ

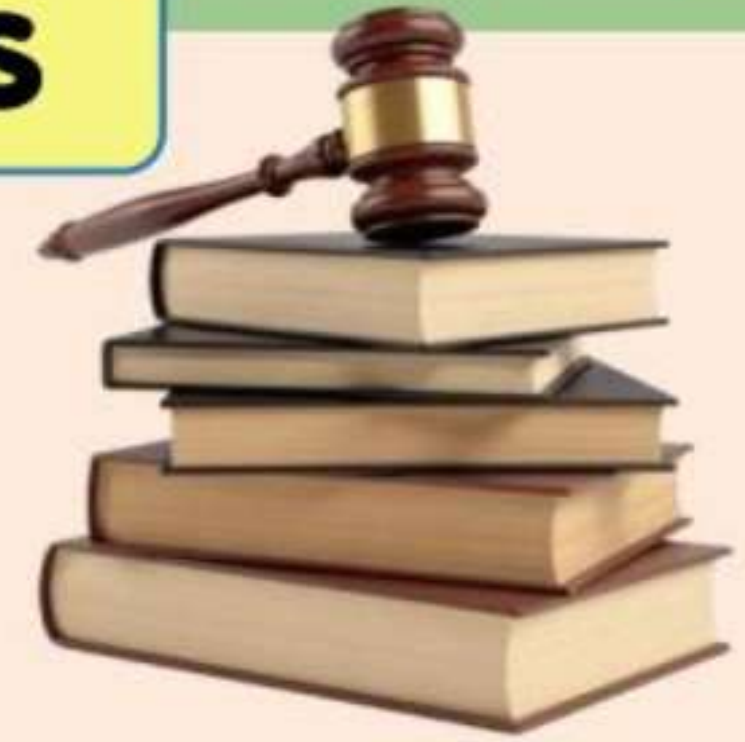
- ✓ **Collective responsibility / सामूहिक ज़िम्मेदारी**
- ✓ **The entire COM is collectively responsible to the LA. / पूरा COM सामूहिक रूप से LA के प्रति ज़िम्मेदार होता है।**
- ✓ **If the assembly passes a no-confidence motion, the whole ministry must resign. / अगर असेंबली अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है, तो पूरी मिनिस्ट्री को इस्तीफा देना पड़ता है।**

Individual Responsibility / व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी:

- ✓ **Each minister is individually responsible for actions in their own department. / हर मंत्री अपने विभाग में किए गए कामों के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होता है।**
- ✓ **CM can advise Governor to remove a minister who disagree with cabinet policy. / CM, गवर्नर को उस मंत्री को हटाने की सलाह दे सकता है जो कैबिनेट की पॉलिसी से सहमत नहीं है।**



Functions & Powers



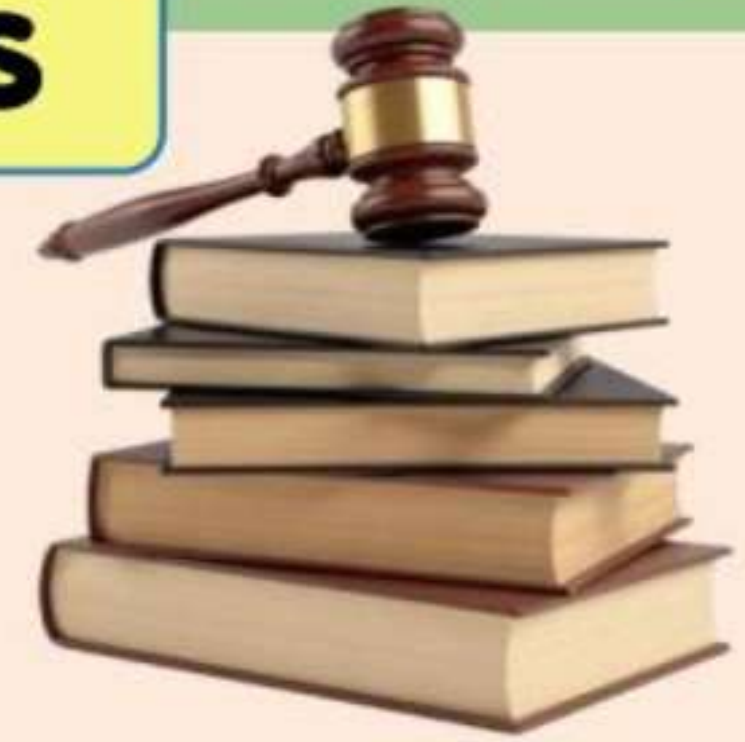
Executive functions / कार्यकारी कार्य :

- **Formulates and implements state policies and programs./**
राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों को बनाता है और लागू करता है।
- **Advises the Governor in appointment and administrative decisions./** राज्यपाल को नियुक्ति और प्रशासनिक निर्णयों में सलाह देता है।

Maximum strength of legislative assembly is 15% of total membership of assembly (91st Constitutional Amendment Act of 2003.

विधान सभा की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्यता का 15% है (91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003)।

Functions & Powers



Legislative functions / विधायी कार्य :

- **Introduces and pilots bills in the Legislative Assembly./** विधान सभा में
बिल पेश करता है और उन्हें पास करवाता है।
- **Responsible for passing of budget and legislative business./** बजट और
विधायी कामकाज पास करवाने के लिए ज़िम्मेदार होता है।

Financial functions / वित्तीय कार्य :

- **Prepares the state Budget and controls financial administration./**
राज्य का बजट तैयार करता है और वित्तीय प्रशासन को नियंत्रित करता है।
- **Money Bills can be introduced only with prior recommendation of**
the Governor (on the advice of CoM)/ मनी बिल केवल राज्यपाल की पूर्व
सिफारिश (CoM की सलाह पर) से ही पेश किए जा सकते हैं।

State legislature

- State legislature occupies a prominent and central position in the political system of a state./ राज्य विधानमंडल किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में एक खास और केंद्रीय स्थान रखता है।
- Article 168 to 212 in part VI of the constitution deal with the organisation, composition, duration, officers, procedures, privileges, powers etc of state legislature. / संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित हैं।
- There are generally two kinds of legislatures followed by the State Legislatures i.e.:/ राज्य विधानमंडलों में आम तौर पर दो तरह के विधानमंडल होते हैं, जैसे:
 1. Unicameral Legislation: It consists of the Governor and the Legislative Assembly (Vidhan Sabha). / एकसदनीय विधानमंडल: इसमें राज्यपाल और विधान सभा (विधान सभा) शामिल होते हैं।
 2. Bicameral Legislation: It consists of Governor, Legislative Council (Vidhan Parishad) and Legislative Assembly/ द्विसदनीय विधानमंडल: इसमें राज्यपाल, विधान परिषद (विधान परिषद) और विधान सभा शामिल होते हैं।

S. Legislature
वि. मंडल

Leg. Council
वि. परिषद

Leg. Assembly
वि. सभा

min 40
max
 $\frac{1}{3}$ of State.
Leg. Assembly
40 Max

min 60
max 500

120
3

State legislature

- At present there are only six states which have **bicameral legislation/ वर्तमान में केवल छह राज्य ऐसे हैं जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है।**
- These States are Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, Maharashtra, Bihar, and Uttar Pradesh./ ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश।

Note: The Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010 to revive the legislative council in the State of Tamil Nadu is yet to be implemented.

तमिलनाडु राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर से शुरू करने के लिए तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट, 2010 को अभी लागू किया जाना बाकी है।

Creation and Abolition of legislative council

Constitutional Provision: The creation and abolition of the State Legislative Council is given in Article 169 of the Indian Constitution.

संवैधानिक प्रावधान: राज्य विधान परिषद का गठन और उसे खत्म करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया है।

Role of Parliament: The Parliament can abolish a legislative council (where it already exists) or create it (where it does not exist), if the legislative assembly of the concerned state passes a resolution to that effect.

संसद की भूमिका: संसद किसी विधान परिषद को (जहां वह पहले से मौजूद है) खत्म कर सकती है या उसे बना सकती है (जहां वह मौजूद नहीं है), अगर संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में एक प्रस्ताव पास करती है।



Composition of two Houses

Legislative Assembly (Vidhan Sabha):

- **Strength:** The Legislative Assembly of the state can have at most 500 constituencies and at least 60 constituencies. / सदस्यों की संख्या: राज्य की विधान सभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं।
- There are several exceptions to the composition of the Legislative Assembly. For example – Mizoram, Sikkim, and Goa which have less than 60 constituencies./ विधान सभा की संरचना में कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए - मिजोरम, सिक्किम और गोवा, जहाँ 60 से कम निर्वाचन क्षेत्र हैं।



Composition of two Houses

500

- **Nomination:** The Governor could nominate one member from the Anglo-Indian community to the Legislative Assembly of State under Article 333 till 2019. However, this was discontinued after the enactment of the 104th Constitutional Amendment Act, 2019./ नामांकन: राज्यपाल 2019 तक अनुच्छेद 333 के तहत एंग्लो-इंडियन समुदाय से एक सदस्य को राज्य की विधान सभा में नॉमिनेट कर सकते थे। हालाँकि, 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया।

552



Election of the members / सदस्यों का चुनाव :

- The Entire State is divided into several territorial constituencies by the **Delimitation Commission.** / पूरे राज्य को डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा कई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएन्सी में बांटा गया है।
- The representatives of the territorial constituencies are elected through the **process of direct election.** / टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएन्सी के प्रतिनिधियों को सीधे चुनाव की प्रक्रिया से चुना जाता है।

Territorial Constituencies / टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएन्सी

- The constituencies are drawn in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is the same **throughout the state.** / कॉन्स्टिट्यूएन्सी इस तरह से बनाई जाती हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएन्सी की आबादी और उसे अलॉट की गई सीटों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में एक जैसा हो।



Tenure of the Assembly

- Mentioned in Article 172 of the Indian Constitution, the Legislative Assembly has a normal term of five years. Its tenure starts from the day of its first meeting./ भारतीय संविधान के आर्टिकल 172 में बताया गया है कि विधान सभा का सामान्य कार्यकाल पांच साल का होता है। इसका कार्यकाल इसकी पहली मीटिंग के दिन से शुरू होता है।
- Authority to Dissolve the Assembly: However, the Governor is authorised to dissolve the assembly at any time (i.e., even before the completion of five years) under circumstances established by the law. / विधान सभा को भंग करने का अधिकार: हालांकि, गवर्नर को कानून द्वारा तय की गई परिस्थितियों में किसी भी समय (यानी पांच साल पूरे होने से पहले भी) विधान सभा को भंग करने का अधिकार है।

Tenure of the Assembly

१०२१

2027

- **Extension of Tenure:** Its tenure can also be extended during the National Emergency./ कार्यकाल बढ़ाना: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है।
- **Maximum Extension Period:** During the period of the National Emergency, the Parliament can extend the tenure of the Legislative Assembly for a period of a maximum one year./ अधिकतम विस्तार अवधि: राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान, संसद विधान सभा का कार्यकाल अधिकतम एक साल के लिए बढ़ा सकती है।
- **Re-election After Emergency:** This means that the assembly should be re-elected within six months after the revocation of the emergency./ आपातकाल के बाद दोबारा चुनाव: इसका मतलब है कि आपातकाल खत्म होने के छह महीने के अंदर विधान सभा का दोबारा चुनाव होना चाहिए।

State Legislative Council (Vidhan Parishad)



- **Strength:** The size of the State Legislative Council cannot be more than 1/3rd of the membership of the State Legislative Assembly. / राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधान सभा की सदस्यता के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता।
- **Minimum Size of the Legislative Council:** Its size cannot be less than 40 members. / विधान परिषद का न्यूनतम आकार: इसका आकार 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकता।
- **The size of the council depends on the size of the assembly of the concerned state.** / परिषद का आकार संबंधित राज्य की विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है।

Here, it should be noted here that although the Constitution has fixed the maximum and the minimum limits, the actual strength of a Council is fixed by Parliament.

यहां यह ध्यान देना ज़रूरी है कि हालांकि संविधान ने मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट तय की हैं, लेकिन किसी काउंसिल की असली संख्या पार्लियामेंट तय करती है।

- **Election of the members:** Out of the total members of the Council, following methods are used to elect members: / सदस्यों का चुनाव: काउंसिल के कुल सदस्यों में से, सदस्यों को चुनने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है:

50 ✓

Total members elected / कुल निर्वाचित सदस्य	Elected By / निर्वाचक
1/3rd of the total members / कुल सदस्यों का 1/3 भाग ✓	• By the members of local bodies in the state like municipalities, district boards, etc. / राज्य की स्थानीय संस्थाओं जैसे नगरपालिकाएँ, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों द्वारा। ✓
1/3rd of the total members / कुल सदस्यों का 1/3 भाग ✓	• By the members of the legislative assembly of the state from amongst persons who are not members of the assembly. / राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा, जो सभा के सदस्य नहीं हैं, उनमें से चुने जाते हैं। ✓
1/12 of the total members / कुल सदस्यों का 1/12 भाग ✓	• By graduates of three years standing and residing within the state. / तीन वर्षों से स्नातक और राज्य के निवासी व्यक्तियों द्वारा। ✓
1/12 of the total members / कुल सदस्यों का 1/12 भाग ✓	• By teachers of three years standing in the state, not lower in standard than secondary school. / राज्य में तीन वर्षों से कार्यरत शिक्षकों द्वारा, जिनकी योग्यता माध्यमिक विद्यालय से कम नहीं है। ✓
1/6 of the total members / कुल सदस्यों का 1/6 भाग ✓	• Nominated by the Governor from amongst persons who have a special knowledge or practical experience of literature, science, art, cooperative movement and social service. / राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से नामित किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। ✓

• **Note: This composition of a legislative council (mentioned in Article 171) as laid down in the Constitution is tentative and not final.** / ध्यान दें: संविधान में बताया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का यह ढांचा (अनुच्छेद 171 में बताया गया) अस्थायी है, फाइनल नहीं।

- **Tenure of the Council: The legislative council is a continuing chamber, same as that of Rajya Sabha. It is a permanent body and is not subject to dissolution.** / काउंसिल का कार्यकाल: लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा की तरह ही एक लगातार चलने वाला सदन है। यह एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता।
- **1/3rd of its members retire on the expiration of every second year. So, a member continues as such for six years.** / इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल के खत्म होने पर रिटायर हो जाते हैं। इसलिए, एक सदस्य छह साल तक सदस्य बना रहता है।
- **The tenure of six years is defined in Section 156 of The Representation of People Act, 1951 and not in the Constitution** / छह साल का कार्यकाल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 156 में परिभाषित है, न कि संविधान में।



- **The retiring members are also eligible for re-election and re-nomination any number of times.** / रिटायर होने वाले सदस्य भी कितनी भी बार दोबारा चुनाव लड़ने और दोबारा नॉमिनेट होने के लिए एलिजिबल हैं।

Sessions of State Legislature

Summoning:

- **The governor from time to time summons each House of state Legislature to meet./** गवर्नर समय-समय पर राज्य विधानमंडल के हर सदन को मीटिंग के लिए बुलाते हैं।
- **The maximum gap between the two sessions of state legislature cannot be more than six months/** राज्य विधानमंडल के दो सेशन के बीच ज़्यादा से ज़्यादा गैप छह महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता।
- **The state legislature should meet at least twice a year./** राज्य विधानमंडल को साल में कम से कम दो बार मिलना चाहिए।

Adjournment / स्थगन :

- An adjournment suspends the work in a sitting for a specified time which may be hours, days or weeks./ स्थगन का मतलब है किसी बैठक में काम को एक तय समय के लिए रोकना, जो घंटे, दिन या हफ्ते हो सकते हैं।
- Adjournment sine die means terminating a sitting of the state legislature for an indefinite period. / अनिश्चित काल के लिए स्थगन का मतलब है राज्य विधानमंडल की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना।

Prorogation / सत्रावसान :

- The Presiding officer (speaker or chairman) declares the House adjourned sine die, when the business of the session is completed./ जब सत्र का काम पूरा हो जाता है, तो पीठासीन अधिकारी (स्पीकर या चेयरमैन) सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित कर देते हैं।
- Within the next few days, the Governor issues a notification for prorogation of the session./ अगले कुछ दिनों में, राज्यपाल सत्र के सत्रावसान के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं।
- However, the Governor can also prorogue the House which is in session. / हालांकि, राज्यपाल चल रहे सत्र वाले सदन का भी सत्रावसान कर सकते हैं।



Dissolution / भंग होना :

- **The Legislative Council being a permanent house, is not subject to dissolution./** लेजिस्लेटिव काउंसिल एक स्थायी सदन होने के कारण, भंग नहीं होती है।
- **Only the legislative assembly is subject to dissolution./** केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही भंग हो सकती है।
- **Unlike, a prorogation, a dissolution ends the very life of the existing House and a new house is constituted after the general elections are held./** स्थगन के विपरीत, भंग होने से मौजूदा सदन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और आम चुनाव होने के बाद एक नया सदन बनता है।

Quorum / कोरम :

- **Quorum is the minimum number of members required to be present in the House before it can transact any business./** कोरम सदन में किसी भी काम को शुरू करने से पहले मौजूद सदस्यों की न्यूनतम संख्या है।
- **It is ten members or one-tenth of the total number of members of the House including the presiding officer, whichever is greater./** यह दस सदस्य या पीठासीन अधिकारी सहित सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा होता है, जो भी ज़्यादा हो।

Language in state legislature / राज्य विधानमंडल में भाषा :

- The constitution has declared the official language of the state or Hindi or English to be the language for transacting business in the state legislature./ संविधान ने राज्य विधानमंडल में कामकाज के लिए राज्य की आधिकारिक भाषा या हिंदी या अंग्रेजी को भाषा घोषित किया है।
- However, the Presiding officer can permit a member to address the house in his/her mother-tongue./ हालांकि, पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

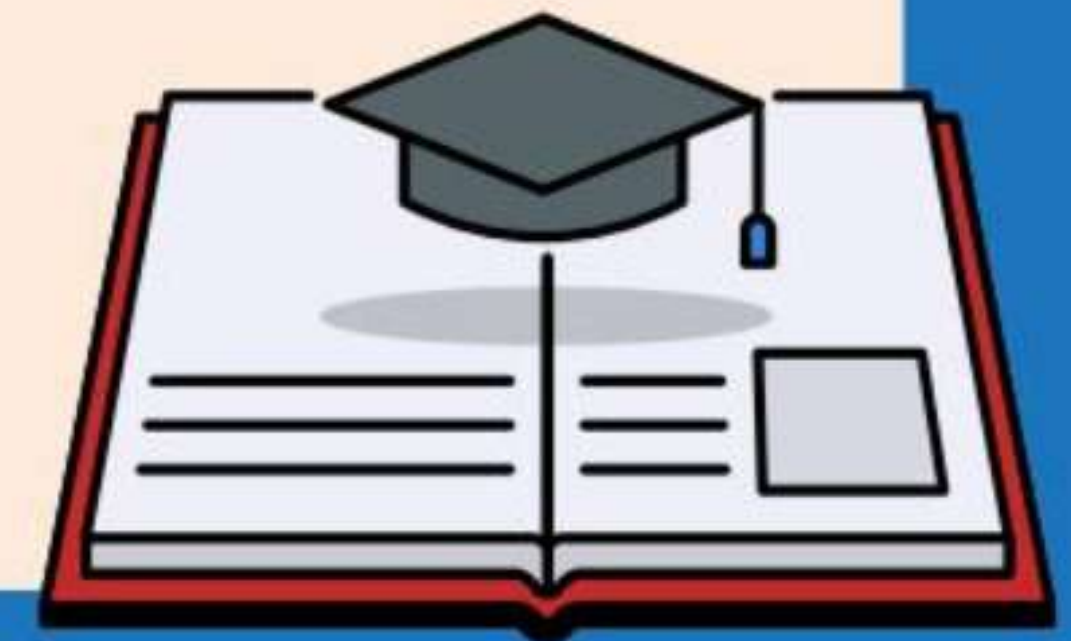


सत्यमेव जयते

Bills in state legislature

Ordinary bills / साधारण बिल :

- **An ordinary bill can originate in either house of the state legislature./** एक साधारण बिल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है।
- **Such a bill can be introduced either by a minister or by any other member./** ऐसा बिल या तो कोई मंत्री या कोई अन्य सदस्य पेश कर सकता है।
- **The bill passes through three stages in the originating House: /** यह बिल शुरू करने वाले सदन में तीन चरणों से गुजरता है:
 1. **First reading /** पहली रीडिंग
 2. **Second reading /** दूसरी रीडिंग
 3. **Third reading /** तीसरी रीडिंग



- **After the bill is passed by the originating House, it is transmitted to the second House for consideration and passage./** जब बिल पहले सदन से पास हो जाता है, तो उसे दूसरे सदन में विचार और पास होने के लिए भेजा जाता है।
- **A bill is deemed to have been passed by the state legislature only when both the Houses have agreed to it, either with or without amendments./** कोई बिल राज्य विधानमंडल द्वारा तभी पास माना जाता है जब दोनों सदन उस पर सहमत हो जाएं, चाहे उसमें संशोधन किए गए हों या नहीं।
- **In case of Unicameral legislature, a bill passed by the legislative assembly is sent directly to the governor for his/her assent./** अगर एक सदनीय विधानमंडल है, तो विधान सभा द्वारा पास किया गया बिल सीधे राज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाता है।



Bills in second House

- In the second House also, the bill passes through all the three stages, that is, first reading, second reading and third reading. / दूसरे सदन में भी, बिल तीनों स्टेज से गुजरता है, यानी पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग।
- When a bill is passed by the legislative assembly and transmitted to the legislative council, the council has four alternatives before it: / जब कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाता है, तो काउंसिल के पास चार ऑप्शन होते हैं:
 1. It may pass the bill without amendments / वह बिल को बिना किसी बदलाव के पास कर सकती है।
 2. It may pass the bill with amendments and return it to the assembly for reconsideration. / वह बिल को बदलावों के साथ पास करके असेंबली को दोबारा सोचने के लिए वापस भेज सकती है।
 3. It may reject the bill / वह बिल को रिजेक्ट कर सकती है।
 4. It may not take any action and thus keep the bill pending. / वह कोई एक्शन न ले और इस तरह बिल को पेंडिंग रख सकती है।



- If the council passes the bill without amendments or the assembly accepts the amendments suggested by the council, the bill is deemed to have been passed by both the Houses and is sent to the Governor for his/her assent./ अगर काउंसिल बिल को बिना किसी बदलाव के पास कर देती है या असेंबली काउंसिल द्वारा सुझाए गए बदलावों को मान लेती है, तो बिल को दोनों सदनों से पास माना जाता है और उसे गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाता है।

Assent of Governor / गवर्नर की मंजूरी:

1. He/she may give his/her assent to the bill/ वह बिल पर अपनी मंजूरी दे सकते हैं।
2. He/she may withhold his/her assent to the bill/ वह बिल पर अपनी मंजूरी रोक सकते हैं।
3. He/she may return the bill for reconsideration of the House or Houses/ वह बिल को सदन या सदनों के फिर से विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।
4. He/she may reserve the bill for consideration of the President./ वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।



Assent of President

- When a bill is reserved by the Governor for the consideration of the President, / जब कोई बिल गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिज़र्व रखा जाता है,
- The president may either give his/her assent to the bill/ तो प्रेसिडेंट या तो बिल पर अपनी मंजूरी दे सकते हैं
- Or withhold his/her assent to the bill/ या बिल पर अपनी मंजूरी रोक सकते हैं
- Or return the bill for reconsideration of the House or Houses of the state legislature./ या बिल को राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।

Assent of President

- **When a bill is returned, the House or Houses have to reconsider it within a period of six months./** जब कोई बिल वापस भेजा जाता है, तो सदन या सदनों को छह महीने के अंदर उस पर फिर से विचार करना होता है।
- **The bill is presented again to the presidential assent after it is passed by the House or Houses with or without amendments./** जब बिल सदन या सदनों द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पास हो जाता है, तो उसे प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए फिर से पेश किया जाता है।

Money Bills



- **A money cannot be introduced in the Legislative Council./** लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल पेश नहीं किया जा सकता।
- **It can be introduced in the Legislative Assembly only and that too on recommendation of the Governor./** इसे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश किया जा सकता है और वह भी गवर्नर की सिफारिश पर।
- **This bill can be introduced only by a minister./** यह बिल सिर्फ एक मंत्री ही पेश कर सकता है।
- **The legislative council has restricted powers with regard to a Money bill. It cannot reject or amend a money bill./** मनी बिल के मामले में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सीमित अधिकार होते हैं। वह मनी बिल को रिजेक्ट या उसमें बदलाव नहीं कर सकती।
- **It can only make recommendations and must return the bill to the legislative assembly with 14 days./** वह सिर्फ सिफारिशें कर सकती है और उसे 14 दिनों के अंदर बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस भेजना होता है।

Articles related to state Legislature

Article No.	Subject-Matter / विषय-वस्तु
Article 168	• Constitution of legislatures in states. / राज्यों में विधानमंडलों का गठन।
Article 169	• Abolition or creation of legislative councils in states. / राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या गठन।
Article 170	• Composition of the Legislative Assembly. / राज्य विधानसभा की संरचना।
Article 171	• Composition of the Legislative Councils. / विधान परिषद की संरचना।
Article 172	• Duration of state legislatures. / राज्य विधानमंडलों की अवधि।
Article 173	• Qualifications for membership of the state Legislature. / राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता।
Article 174	• Sessions of the state legislature, prorogation and dissolution. / राज्य विधानमंडल के सत्र, स्थगन और विघटन।
Article 175	• Right of Governor to address and send message to the House or Houses. / राज्यपाल का सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार।
Article 176	• Special address by the Governor. / राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन।

Article No.	Subject-Matter / विषय-वस्तु
Article 177	Rights of ministers and advocate general as respects the houses. / सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार।
Article 178	The Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly. / विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
Article 179	Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker. / अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की रिक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना।
Article 180	Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as Speaker. / उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अधिकार कि वह अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करे या अध्यक्ष के रूप में कार्य करे।
Article 181	The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his/her removal from office is under consideration. / जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब वे अध्यक्षता नहीं करेंगे।
Article 182	The Chairman and Deputy Chairman of Legislative Council. / विधान परिषद के सभापति और उपसभापति।
Article 183	Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Chairman and Deputy Chairman. / सभापति और उपसभापति के पदों की रिक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना।

Article No.	Subject-Matter / विषय-वस्तु
Article 184	Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as Chairman. / उपसभापति या अन्य व्यक्ति के अधिकार कि वह सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करे या सभापति के रूप में कार्य करे।
Article 185	The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his/her removal from office is under consideration. / जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब वे अध्यक्षता नहीं करेंगे।
Article 186	Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman. / अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते।
Article 187	Secretariat of state legislature. / राज्य विधानमंडल का सचिवालय।
Article 188	Oath or affirmation by members. / सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
Article 189	Voting in houses, power of houses to act notwithstanding vacancies and quorum. / सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद सदनों की कार्यवाही करने की शक्ति।

Article No.	Subject-Matter / विषय-वस्तु
Article 190	• Vacation of seats. / सीटों का रिक्त होना।
Article 191	• Disqualifications for membership. / सदस्यता के लिए अयोग्यता।
Article 192	• Decision on questions as to disqualifications of members. / सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय।
Article 194	• Powers, privileges etc. of the house of legislatures and of the members and committees thereof. / विधानमंडल के सदनों और उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।
Article 195	• Salaries and allowances of members. / सदस्यों के वेतन और भत्ते।
Article 196	• Provisions as to introduction and passing of bills. / विधेयकों के प्रस्तुतीकरण और पारित होने से संबंधित प्रावधान।
Article 197	• Restrictions on powers of Legislative Council as to bills other than Money Bills. / धन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध।

Article No.	Subject-Matter / विषय-वस्तु
Article 198	• Special procedures in respect of Money Bills. / धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया।
Article 199	• Definition of Money Bill. / धन विधेयक की परिभाषा।
Article 200	• Assent to Bills. / विधेयकों पर स्वीकृति।
Article 201	• Bills reserved for consideration. / विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयक।
Article 202	• Annual Financial Statement. / वार्षिक वित्तीय विवरण।
Article 203	• Procedure in Legislature with respect to estimates. / अनुमान से संबंधित विधानमंडल में प्रक्रिया।
Article 204	• Appropriation Bills. / विनियोग विधेयक।
Article 205	• Supplementary, additional or excess grants. / अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान।
Article 206	• Vote on account, votes of credit and exceptional grants. / लेखानुदान, ऋण अनुदान और असाधारण अनुदान।

Article No.	Subject-Matter / विषय-वस्तु
Article 207	Special provisions as to financial bills. / वित्तीय विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान।
Article 208	Rules of procedure. / प्रक्रिया के नियम।
Article 209	Regulation by law of procedure in the Legislature of the state in relation to financial business. / राज्य की विधानमंडल में वित्तीय कार्य से संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन।
Article 210	Language to be used in the legislature. / विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा।
Article 211	Restriction on discussion in the legislature. / विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध।
Article 212	Courts not to inquire into proceedings of the Legislature. / न्यायालयों को विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार नहीं।
Article 213	Power of Governor to promulgate Ordinances during recess of Legislature. / विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति।



1. In case of a conflict between Central and State law on a Concurrent List subject, the State law prevails only if:

समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होने पर राज्य का कानून तभी प्रभावी होता है जब:

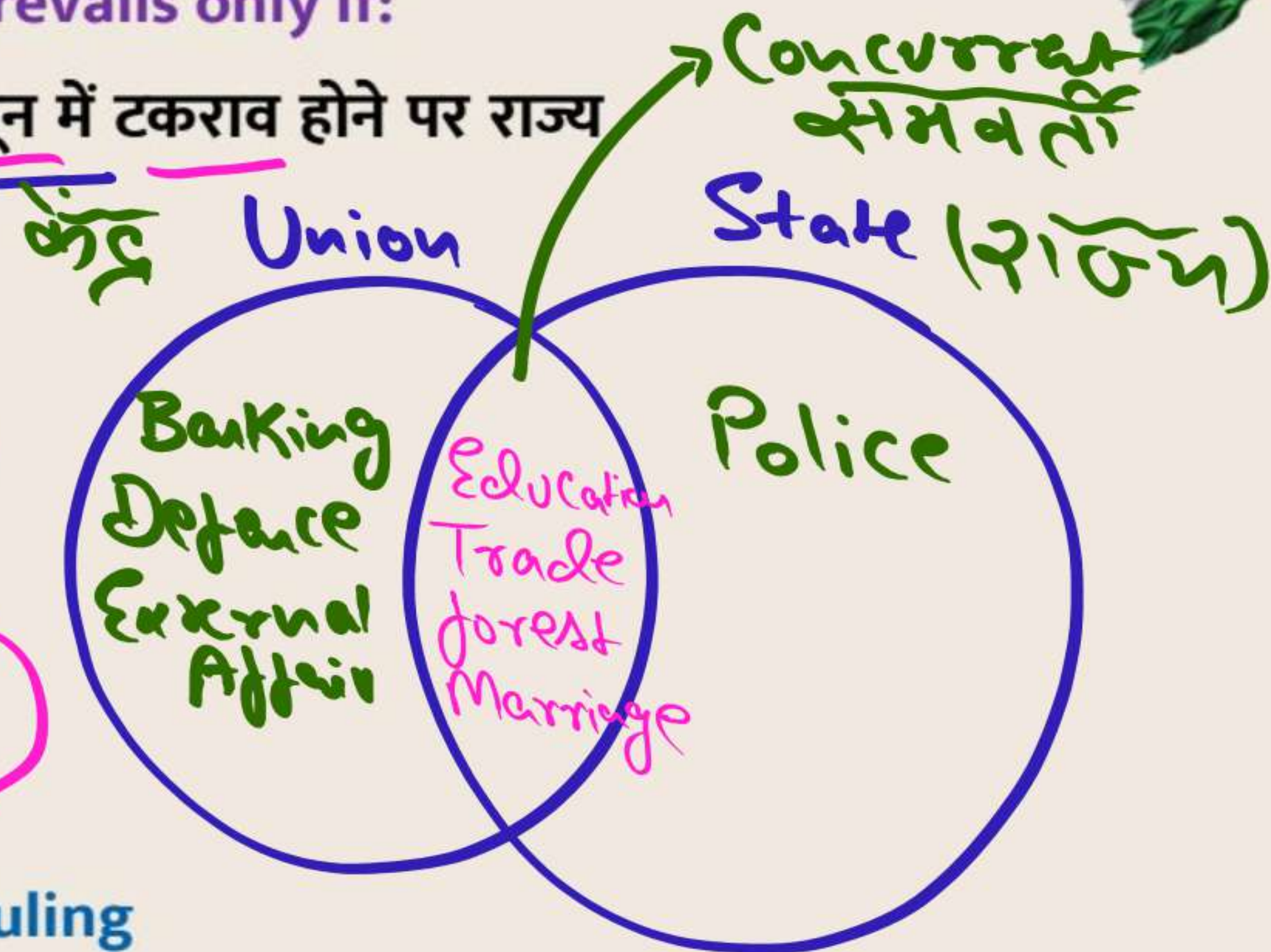
(SSC Phase 13, 24/07/2025)

(a) It is passed by a two-thirds majority
इसे दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया हो *

(b) It has received Presidential assent
इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो

(c) It is supported by a Supreme Court ruling
इसे सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन प्राप्त हो

(d) The Rajya Sabha passes it / राज्यसभा इसे पारित करे





ANSWER

B



A 40%
B 45%
C 15%

2. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

[Ssc phase 13, 29/07/2025]

1. President can dissolve Lok Sabha on his own discretion. / राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। (X)

2. Governor appoints Chief Minister in a hung assembly./ टंगी हुई विधानसभा (Hung Assembly) की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। (✓)

3. Governor has no role in Money Bills.

मनी बिल में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। (X)

Which of the above is/are correct?

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 2 only / केवल 2

(b) 1 only / केवल 1

(c) 3 only / केवल 3

(d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

A



ANSWER

A



3. Which state has a bicameral legislature?

निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है?

(SSC Phase 13, 31/07/2025)

(a) Tamil Nadu / तमिलनाडु

(b) West Bengal / पश्चिम बंगाल

(c) Maharashtra / महाराष्ट्र

(d) Gujarat / गुजरात

L.C. L.P.V.



ANSWER

C



4. What is the maximum number of members in a State Legislative Assembly as per the Constitution?

संविधान के अनुसार, किसी राज्य की विधान सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

60

[Ssc phase 13, 29/07/2025]

(a) 450

(b) 500

(c) 550

(d) 600

B



ANSWER

B

5. Who is the first woman to become the Chief Minister of an Indian state?

किस महिला ने किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया? ✓

(SSC Phase 13, 31/07/2025)

(a) Anwara Taimur / अनवारा तैमूर

(b) Sucheta Kripalani / सुचेता कृपलानी

(c) Shashikala Kakodkar / शशिकला काकोडकर

(d) Nandini Satpathy / नंदिनी सतपथी

1st Gov. female
Sarojini Naidu
(U.P.)

→ U.P.
→ 1963-67

ANSWER

B

6. Who has the power to appoint the Chief Minister (CM) of a state in India?

भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री (CM) की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है?

(SSC Phase 13, 30/07/2025)

- (a) President of India / भारत के राष्ट्रपति
- (b) Prime Minister / प्रधानमंत्री
- (c) Chief Justice of India / भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (d) Governor of the State / राज्य का राज्यपाल





ANSWER

D



7. Who acts as the link between the Governor and the State Council of Ministers?

राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी (link) के रूप में कौन कार्य करता है?

(SSC Phase 13, 28/07/2025)

(a) Chief Secretary / मुख्य सचिव

(b) Chief Minister / मुख्यमंत्री

(c) Speaker / अध्यक्ष

(d) Advocate General / महाधिवक्ता



ANSWER

B



8. What is the tenure of a Governor in an Indian state?

भारतीय राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है?

(SSC Phase 13, 26/07/2025)

(a) 3 years / 3 वर्ष

(b) 5 years / 5 वर्ष

(c) 6 years / 6 वर्ष

(d) Until retirement / सेवानिवृत्ति तक



ANSWER

B



9. Which article of the Constitution provides for the State Legislative Assemblies?

संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं के प्रावधान से संबंधित है?

(SSC Phase 13, 29/07/2025)

(a) Article 168 / अनुच्छेद 168

(b) Article 170 / अनुच्छेद 170

(c) Article 172 / अनुच्छेद 172

(d) Article 174 / अनुच्छेद 174



ANSWER

A

10. Which of the following is a subject under the State List?

निम्नलिखित में से कौन-सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है?

(SSC Steno, 06/08/2025, Shift-1)

(a) Banking / बैंकिंग

Union

(b) Public Order / लोक व्यवस्था

State

(c) Defence / रक्षा

Union

(d) Education / शिक्षा

Concurrent

ANSWER

B



11. Statement 1: Governor is state's constitutional head.

कथन 1: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।



Statement 2: He acts solely on Council's advice.

कथन 2: वह केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है।



Which of the above statements holds true regarding Governor's executive powers? / राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(SSC Steno, 08/08/2025, Shift-2)

(a) Both 1 and 2 / 1 और 2 दोनों

(b) Only 1 / केवल 1

(c) Only 2 / केवल 2

(d) Neither 1 nor 2 / न तो 1 और न ही 2



ANSWER

B



12. Which article provides for the appointment of Governors in India?

भारत में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

(SSC Steno, 07/08/2025, Shift-1)

(a) Article 170 / अनुच्छेद 170

(b) Article 154 / अनुच्छेद 154

(c) Article 155 / अनुच्छेद 155

(d) Article 168 / अनुच्छेद 168

→ Executive power
of Governor



ANSWER

C



13. The President is elected by an electoral college, while the Governor is:

राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल:

(SSC CGL Tier-1, 13 Sep 2025, Shift-2)

(a) Directly elected / सीधे चुना जाता है ✗

(b) Appointed by the President / राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है

(c) Nominated by Supreme Court / सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित किया जाता है ✗

(d) Chosen by State Assembly / राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है ✓



ANSWER

B



14. Which discretionary power allows a Governor to reserve a bill passed by the state legislature for the consideration of the President?

राज्यपाल की कौन-सी विवेकाधीन शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने की अनुमति देती है?

(SSC Steno, 07/08/2025, Shift-3)

(a) To send a report to the President for the imposition of President's Rule. /

राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना।

(b) To reserve a bill for the President's consideration.

किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना।

(c) To grant pardon in certain cases. / कुछ मामलों में क्षमा प्रदान करना।

(d) To summon, prorogue, and dissolve the state legislative assembly.

राज्य विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना और भंग करना।



ANSWER

B

15. After Bill is passed by State, Governor may forward it to:

राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल इसे किसे भेज सकते हैं?

(SSC CGL Tier-1, 22 Sep 2025, Shift-3)

(a) Chief Minister / मुख्यमंत्री ✗

(b) Speaker / अध्यक्ष ✗

(c) President / राष्ट्रपति ✓

(d) Prime Minister / प्रधानमंत्री ✗

ANSWER

C